जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

जालोर

Rashtradoot

फोनः- 226422, 226423 फैक्सः- 02973-226424 वर्षः 20 संख्याः 169 प्रभात जालोर, गुरुवार 25 सितम्बर, 2025 पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

प्रधानमंत्री आज बाँसवाड़ा में परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास करेंगे

मुख्यमंत्री भजनलाल ने प्रधानमंत्री की यात्रा की तैयारियों का विस्तृत निरीक्षण किया

जयपुर (कासं), 24 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बांसवाड़ा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मोदी, राजस्थान को 1 लाख 8 हजार 468 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देंगे। साथ ही 1 लाख 22 हजार 670 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण भी करेंगे।

बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बांसवाड़ा के नापला पहुंचे। उन्होंने

- **प्रधानमंत्री जल संसाधन विभाग की 20,833 करोड़ रूपए की परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। इनमें ईसरदा के जयपुर, भरतपुर और अलवर जिलों तक फीडर निर्माण, बीसलपुर व ब्रह्मणी बैराज जैसे महत्वपूर्ण जल प्रोजैक्ट शामिल हैं।**

प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने पेयजल, पार्किंग व्यवस्था तथा जनसभा में आमजन के बैठने की तैयारियों की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को बांसवाड़ा के नापला में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ भी मौजूद थे।

साथ ही पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों से संवाद को लेकर की गई तैयारियों का भी जायजा लिया। इस अवसर पर सांसद मदन राठौड़, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण प्रवीण गुप्ता सहित संभागीय व जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

ज्ञात रहे कि गुरूवार को प्रधानमंत्री बांसवाड़ा में 42 हजार करोड़ रुपए की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एसआई पेपर लीक मामले में 3 और प्रोबेशनर गिरफ्तार

जयपुर, 24 सितम्बर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने सब इंस्पेक्टर (एसआई) परीक्षा-2021 पेपर लीक मामले में कार्रवाई करते हुए तीन और प्रोबेशनर (ट्रेनी) एसआई को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान एसओजी को कुछ सबूत मिले, जिसके आधार पर तीनों को पूछताछ के लिए मुख्यालय बुलाया गया और फिर तीनों ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों सॉल्व पेपर पढ़कर परीक्षा पास करने का आरोप है, एसओजी इस

- **एसओजी को प्राप्त सबूतों के अनुसार, तीनों पर लीक हुए सॉल्व पेपर पढ़कर एसआई भर्ती में चयनित होने का आरोप है।**

मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है और अब तक 59 प्रोबेशनर एसआई समेत 130 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी एसओजी) वीके सिंह ने बताया कि एसआई भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक मामले में कार्रवाई करते हुए परमेश चौधरी (26) निवासी मालियों की ढाणी, ग्राम त्योदा, थाना सांभर, जयपुर ग्रामीण, वर्तमान में पुलिस लाइन टोंक; मनोहर सिंह (25) निवासी ग्राम सेडीया, थाना करडा, जालोर, वर्तमान में पुलिस लाइन कोटा शहर, और मनोहर लाल (26) निवासी वियो का गोलिया, ग्राम पुनासा, थाना भीनमाल, जालोर, वर्तमान में पुलिस लाइन सिरोही में तैनात को गिरफ्तार किया है।

एसओजी-एटीएस के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि अनुसंधान में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मल्लिकार्जुन खड़गे दो साल के शासन के बाद ही थके-थके क्यों हैं?

वे पुराने बुर्जुग नेताओं, जैसे अंबिका सोनी, मीरा कुमार आदि की विदाई नहीं कर पाये, सीडब्ल्युसी से और न ही गौरव गोगोई, रणदीप सुरजेवाला, चरणजीत सिंह चन्नी को शिफ्ट कर पाये

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 सितम्बर। भले ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के 88वें अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अगले महीने अपने कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे करने जा रहे हों, लेकिन कांग्रेस पर लंबे समय से नजर रखने वाले एक पर्यवेक्षक का कहना है कि यह पार्टी अभी भी अनिश्चित भविष्य, निष्क्रियता और कई राज्यों में आंतरिक खींचतान से जूझ रही है - हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान से लेकर असम, केरल और बंगाल तक, जहां अगले वर्ष की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं।

पिछले छह महीनों से भी अधिक समय से कांग्रेस नेतृत्व, जिसमें खड़गे और गांधी परिवार शामिल हैं, कांग्रेस कार्य समिति (सी.डब्ल्यु.सी.) के कुछ उम्रदराज सदस्यों को हटाकर नए नेताओं को जगह देने में विफल रहे हैं। इन नए नेताओं में शामिल हैं: रजनी पाटिल (हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ की प्रभारी), बी.के. हरिप्रसाद (हरियाणा), हरीश चौधरी (मध्य प्रदेश), गिरीश चोडनकर (तमिलनाडु और पुडुचेरी), अजय कुमार लल्लू (ओडिशा), के. राजू (झारखंड), मीनाक्षी नटराजन (तेलंगाना), सप्तगिरी शंकर उलक (मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैंड), और कृष्ण

- **एंटनी, अंबिका सोनी, मीरा कुमार के सीडब्ल्युसी में बने रहने का कारण है, सोनिया गांधी से नज़दीकी। गोगोई, सुरजेवाला व चन्नी अपने-अपने प्रदेश में कांग्रेस के मु.मंत्री का चेहरा बनना चाहते हैं। अतः उन्हें भी सीडब्ल्युसी से हटाकर, उनका महत्व कम करने का कोई मतलब नहीं निकलता।**
- **खड़गे की टीम, रजनी पटेल, हरिप्रसन्न, हरीश चौधरी, गिरीश चौडनकर, अजय कुमार लालू, के.राजू, मीनाक्षी नटराजन, सप्तगिरी और कृष्णा अल्लूवारु, अभी पूर्ण महत्व नहीं पा सके।**
- **इस असमंजस की स्थिति में कांग्रेस की सभी प्रांतीय इकाईयों में आंतरिक कलह खत्म होने का नाम नहीं लेती और बाकायदा बरकरार है।**
- **और यह ही कारण है कि राहुल गांधी की 1,300 किलोमीटर ''वोट अधिकार यात्रा'' काफी सफल रही, पर अंतर्कलह के कारण सफलता को वोटों में तब्दील करना मुश्किल हैं।**

अल्लावरु (बिहार)।

सोनिया गांधी के करीबी माने जाने वाले ए. के. एंटनी, अंबिका सोनी, मीरा कुमार और कुछ अन्य अब भी बने हुए हैं और गौरव गोगोई, रणदीप सुरजेवाला और चरणजीत सिंह चन्नी को हटाने की कोशिशें भी आंतरिक समीकरणों के चलते सफल नहीं हो पाईं। गौरव गोगोई असम में पार्टी का चेहरा हो सकते हैं, जबकि सुरजेवाला और चन्नी क्रमशः हरियाणा और पंजाब में पार्टी की कमान संभालना चाहते हैं।

कांग्रेस के संविधान के अनुसार, एआईसीसी के महासचिवों का सीडब्ल्युसी सदस्य होना आवश्यक है। जब तक उन्हें सीडब्ल्युसी में नहीं लिया जाता, तब तक उन्हें ''प्रभारी'' की उपाधि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'बिहार का मानस बदलाव का है, परिवर्तन निश्चित है'

कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने पटना में सीडब्ल्युसी की बैठक के बाद प्रेसवार्ता में कहा

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 सितंबर। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने बुधवार को कहा कि बिहार में बदलाव निश्चित है और उन्होंने चुनाव आयोग से आगामी विधानसभा चुनावों को निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से कराने की जिम्मेदारी निभाने का आग्रह किया।

पायलट ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ और एच-1बी वीज़ा शुल्क में एकमुश्त बढ़ोतरी जैसे फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि दोनों नेताओं की दोस्ती भारत के लिए ''बहुत महंगी'' साबित हो रही है।

सचिन पायलट ने पटना के ऐतिहासिक सदाकत आश्रम में कांग्रेस कार्यसमिति की विस्तारित बैठक के बाद

- **पायलट ने आयोग से कहा कि बिहार में वोट अधिकार यात्रा को भारी समर्थन मिला है और कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी।**
- **तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने पर पायलट ने कहा, समय आने पर इस बारे में निर्णय लिया जाएगा।**
- **पायलट ने जीएसटी पर पूछे सवाल के जवाब में कहा, कांग्रेस और राहुल गांधी शुरु से कह रहे थे, यह गब्बर सिंह टैक्स है, एक गलती को सुधारने में 8 साल लग गए।**

आयोजित प्रेस वार्ता में यह बयान दिया। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की।

सचिन पायलट ने कहा, 2017 से लगातार आठ वर्षों तक कांग्रेस और राहुल गांधी ने इसे ''गब्बर सिंह टैक्स'' कहा और गलतियों की ओर इशारा किया। जब मनमोहन सिंह सरकार जीएसटी लाना चाहती थी, तब भाजपा ने इसका विरोध किया और सत्ता में आते ही यू-टर्न ले लिया।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

17 फरवरी से होंगी सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं

नयी दिल्ली, 24 सितंबर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 2026 में होने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के लिए बुधवार को संभावित तारीख घोषित की।

सीबीएसई की ओर से जारी संभावित तारीखों के अनुसार बोर्ड

- **सीबीएसई ने 2026 से होने वाली 10 वीं 12 वीं बोर्ड की परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित किया है कार्यक्रम के अनुसार 17 फरवरी से 15 मार्च के बीच बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएगी।**

परीक्षाएं 17 फरवरी से 15 मार्च 2026 के बीच आयोजित हो सकती हैं। उन्होंने बताया है कि इन परीक्षाओं में 45 लाख से अधिक विद्यार्थी हिस्सा ले

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने एस.आई. भर्ती रद्द करने पर अंतरिम रोक हटाई

शीर्ष अदालत ने आदेश में कहा कि, ''राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ 3 माह में इस मामले की सुनवाई कर दायर अपीलों का निस्तारण करे''

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 24 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने 859 पदों की एस.आई. भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ के 8 सितंबर के उस अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग कराने की छूट दी गई थी। शीर्ष अदालत ने, हाईकोर्ट की खंडपीठ को कहा है कि वह इस मामले में दायर अपीलों का निपटारा 3 महीने में करे।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि खंडपीठ के समक्ष मूल अपीलों में अंतिम फैसला नहीं होने तक किसी भी चयनित अभ्यर्थी को ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश बुधवार को कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की एसएलपी पर दिया।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर

- **हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग की छूट देने के आदेश पर भी रोक लगाई।**
- **ज्ञात रहे कि एकलपीठ ने एस.आई.भर्ती पेपरलीक मामले में एस.आई.टी की जांच रिपोर्ट को आधार बनाते हुए 28 अगस्त को इस परीक्षा को रद्द करने के आदेश दिए थे।**
- **इस रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट था कि आर.पी.एस.सी. के सदस्य स्वयं पेपरलीक में लिप्त थे और उन्होंने अपने पुत्र-पुत्री समेत कई लोगों को पेपर मुहैया करवाया था।**

अपील में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव शकधर और उनके सहायक अधिवक्ता हरिंदर नील पैरवी के लिए उपस्थित हुए थे।

याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट राजीव शकधर ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि, राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए चयनित अभ्यर्थियों को फील्ड ट्रेनिंग कराने की छूट दी है। जबकि फील्ड ट्रेनिंग में कुछ हद तक ट्रेनी एस.आई. को स्वतंत्र निर्णय और काम करने की छूट दी जाती है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि एकलपीठ ने पेपरलीक की जांच के संबंध में गठित एस.आई.टी. रिपोर्ट का गंभीरता से विश्लेषण कर परीक्षा रद्द करने और आर.पी.एस.सी. अधिकारियों को 2021 में जारी विज्ञिप्ति के आधार पर पुनः परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाने के आदेश दिए थे।

याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि, यह मामला जनहित से जुड़ा हुआ है और मामले की जांच में स्पष्ट हुआ है कि एस.आई. भर्ती परीक्षा के पेपरलीक में स्वयं आर.पी.एस.सी. के सदस्य लिप्त थे। इन्हीं आरपीएससी सदस्यों के पुत्र-पुत्री को प्रश्नपत्र उपलब्ध करवाए गए थे, इन्हीं पेपर्स को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रेल कर्मचारियों को मिलेगा 78 दिन का बोनस

नयी दिल्ली, 24 सितंबर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल कर्मचारियों को दीपावली पर 78 दिन का बोनस देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को यहां संवाददाता

- **रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की मीटिंग में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।**

सम्मेलन में यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारतीय आईटी प्रोफैशनल्स अब कैनडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंगलैण्ड, यूएई, सिंगापुर की ओर भी देख रहे हैं

पर, ये देश एक समान नहीं, नौकरियों की दृष्टि से

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 सितम्बर। अमेरिका द्वारा प्रस्तावित नई वेतन-आधारित एच-1 बी वीज़ा चयन प्रणाली भारत के कई युवा प्रोफैशनल्स और एम्प्लॉयर्स को अन्य विकल्पों की तरफ रुख करने पर मजबूर करेगी।

इस नई व्यवस्था में लैवल 1 और लैवल 2 वेतन वाली नौकरियों के आवेदकों की चयन की संभावना घट जाएगी। यह वो ब्रैकेट (श्रेणी) है जिसमें हाल ही में स्नातक बने, जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और प्रवेश-स्तरीय आईटी नौकरियां आती हैं। इससे अमेरिका अब शुरुआती करियर वाले प्रोफैशनल्स और उन स्टार्टअप्स के लिए कम आकर्षक हो जाएगा जो बड़ी टेक कंपनियों जैसी सैलरी नहीं दे सकते।

यह प्रस्ताव, जिसमें एक बड़ा नया शुल्क भी शामिल है, उम्मीदवारों और एम्प्लॉयर्स को सस्ते, आसान और तेज़ विकल्पों की ओर रुख करने को मजबूर करेगा।

कैनडा इस बदलाव का सबसे बड़ा तात्कालिक लाभार्थी दिख रहा है। उसका ''एक्सप्रेस एंट्री'' पॉइंट सिस्टम और प्रांतीय नामांकन कार्यक्रम (प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम) टैंपटेरी वर्क से परमानैंट रैज़िडैंसी तक जाने का साफ और तेज़ रास्ता देता है। ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम से एम्प्लॉयर्स बहुत जल्दी वर्क परमिट दिला सकते हैं। कैनडा पहले से ही अपनी छवि ''कुशल प्रतिभा

- **कैनडा व आस्ट्रेलिया में नौकरी पेशे वालों के लिए एंट्री साफ-सुथरी है, जटितलाएं कम हैं।**
- **यूरोप (जर्मनी, ब्रिटेन) में नये एंट्री लैवल आईटी प्रोफैशनल्स के लिये, यूरोप की लाइफ स्टाइल एक आकर्षण है। पर, जर्मनी में भाषा की दिक्कत जरूर है।**
- **सिंगापुर व यूएई में वेतन भी ठीक है तथा भारत से कम दूरी एक अच्छा विकल्प प्रस्तुत करते हैं।**
- **ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया व सिंगापुर थोड़े सीनियर व अच्छा वेतन पाने वाले प्रोफैशनल्स के लिये ज्यादा आकर्षण हैं। पर, एंट्री लैवल के प्रोफैशनल्स के लिए सिंगापुर व ऑस्ट्रेलिया थोड़े पहुँच से दूर हैं।**

के अनुकूल'' देश की बना चुका है और अमेरिकी नीतिगत कदमों के बाद से भर्ती एजेंसियां कैनडा को एच -1 बी का विकल्प बताकर प्रचार कर रही हैं। उन भारतीयों के लिए, जो आसान स्थायी निवास (परमानैंट रेज़िडैंसी/ पी.आर.) और परिवार की स्थिरता चाहते हैं, कैनडा सबसे आकर्षक नज़र आता है।

ऑस्ट्रेलिया अब भी उन मिड-करियर प्रोफैशनल्स को आकर्षित करता है जो पॉइंट सिस्टम की तय शर्तें पूरी कर सकते हैं। सरकार समय-समय पर अपनी ''स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट'' अपडेट करती है और हाल ही में वीज़ा रुल्स को उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के लिए बदला गया है जहां कर्मचारियों की कमी है। कई स्किल्ड माइग्रैंट्स के लिए ऑस्ट्रेलिया में स्थायी निवास (पी.आर.) का रास्ता साफ है, पर यह प्रक्रिया कैनडा से धीमी और अधिक नियमबद्ध हो सकती है, और कुछ वीज़ा में वेतन की न्यूनतम सीमा काफ़ी ऊँची हो सकती है।

जर्मनी का ई.यू. ब्लू कार्ड, तय वेतन सीमा और त्वरित स्थायी निवास (पी.आर.) विकल्पों के साथ, इंजीनियरों और डेटा वैज्ञानिकों के लिए

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राज्यसभा की 5 सीटों का चुनाव 24 अक्टूबर को

नयी दिल्ली, 24 सितम्बर। केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से चार तथा पंजाब से एक राज्यसभा सीट के लिए 24 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा।

चुनाव आयोग ने बुधवार को यह

- **केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की चार तथा पंजाब की एक राज्यसभा सीट के लिए 13 अक्टूबर को नामांकन भरा जाएगा।**

जानकारी देते हुए बताया कि इस बारे में छह अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी और 13 अक्टूबर तक उम्मीदवार नामांकन कर सकेंगे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)